दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

फरवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण 3
- मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू 3
- राम वन गमन पथ पुनरवलोकन पुस्तक का विमोचन 4
- राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज 4
- विद्युत कार्मिकों की पेंशन योजना में कंपनी के मासिक अंशदान में हुई वृद्धि 4
- रामसर साइट भोज वेटलैंड में शीतकालीन पक्षी गणना हुई पूर्ण 5
- डिजिटल ट्रांजेक्शन : देश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अव्वल 5
- मध्य प्रदेश के तीन स्थानों के नाम परिवर्तन को केंद्र की मंजूरी 6
- मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिन्दी में पढ़ाने की तैयारी प्रारंभ 6
- राज्य सरकार इस वर्ष से 'मध्य प्रदेश रत्न', 'मध्य प्रदेश गौरव' और 'मध्य प्रदेश श्री' पुरस्कार प्रारंभ करेगी 7
- स्टार्टअप एक्सपो-2022 7
- प्रोजेक्ट मीराई का वर्चुअली शुभारंभ 8
- स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय 8
- राज्य शासन द्वारा 4 नई नगर परिषदें गठित 8
- मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 9
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाएँ पुरस्कृत 9
- शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिये प्रदेश के छ: अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार 10
- ग्वालियर में बेबी फीडिंग सेंटर शुरू 10
- इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट (आईडीपी) पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन 11
- मध्य प्रदेश में मिले डायनासोर के अंडे 11
- भारत भवन की 40वीं वर्षगाँठ समारोह का शुभारंभ 12
- विंध्य एवं महाकौशल क्षेत्र को मिली नई ट्रेनों की सौगात 12
- पत्रकारिता विश्वविद्यालय में स्थापित होगा 'सामुदायिक रेडियो कर्मवीर' 13
- पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने लागू किया पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम 13
- मध्य प्रदेश के मोहम्मद अरशद खान आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम में शामिल 14
- इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर 14
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का किया लोकार्पण 14
- केन-बेतवा लिंक परियोजना 15
- भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज 15
- MPPSC परीक्षा में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक 16
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज 17
- मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय 17
- जल जीवन मिशन में कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के लिये 45 करोड़ रुपए स्वीकृत 18
- पर्यटन बोर्ड का साहस संस्था के साथ हुआ एमओयू 18
- 48वाँ खजुराहो नृत्य समारोह-2022 19
- इंदौर में गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण 20
- नकली फिंगर प्रिंट की समस्या का समाधान 20
- मध्य प्रदेश में इंदौर HIV और एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में पहले नंबर पर 21
- बटेश्वर के मंदिरों का पुनरुद्धार 22
- 'वैद्य आपके द्वार' टेलीमेडिसिन ऐप को मिला राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड 22
- प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना 22
- शिवपुरी में खुलेगी देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी 23
- हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पायलेट प्रोजेक्ट जीएमसी से होगा शुरू 23
- 'हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणास्रोत' पुस्तिका का लोकार्पण 24

नोट :

मध्य प्रदेश

होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 31 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण किया।

प्रनुख बिंदु

- शिल्प होमगार्ड मुख्यालय के शिल्प उपवन में देश के शीर्षस्थ शिल्पकारों द्वारा होमगार्ड लाइन में पत्थरों को तराशकर शिल्पांकन किया गया है।
- शिल्प उपवन में विघ्न विनाशक गणेश, कामधेनु, शब्द ब्रह्म, चालाक पक्षी, शिवशक्ति, प्रकृति तथा उल्कापिंड रूपी पत्थरों के श्रेष्ठ जीवंत प्रतिस्थापित किये गए हैं। पाषाण (पत्थरों) में रचे गए ये नयनाभिराम शिल्प ईश्वर, प्रकृति और इंसान के रिश्तों का बखूबी एहसास कराते हैं।
- शिल्प उपवन लोकार्पण समारोह में प्रदेश के 4 डिवीजन को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की चाबियाँ सौंपी गईं। ग्वालियर के डिवीजनल कमांडेंट मनीष सिंह चौहान, जबलपुर के रोहिताश पाठक, भोपाल की ऊषा डामोर और उज्जैन की प्रीति बाला सिंह ने चाबियाँ प्राप्त कीं।
- इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के कार्य को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिये सभी जिलों को टैबलेट प्रदान किये गए।
- इस कार्यक्रम में 10 जिलों- भोपाल, इंदौर, दमोह, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, शाजापुर, सतना, उमरिया और कटनी के अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से टैबलेट प्रदान किये गए।
- होमगार्ड मुख्यालय में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आपदा के समय में होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी देखी और संकट के समय में उपयोग में आने वाले आपदा प्रबंध के आधुनिक उपकरणों का अवलोकन भी किया।

मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू

चर्चा में क्यों?

- 30 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय सीधी भर्ती में ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया।

प्रनुख बिंदु

- सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, जो पद खाली रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिये 16%, अनुसूचित जनजाति के लिये 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये 27%, ईडब्ल्यूएस के लिये 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिये कुल 33 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।
- मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। यह आरक्षण 8 मार्च, 2019 की तिथि से लागू माना जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू माना जाएगा।
- इससे पूर्व 9 सितंबर, 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू किया था, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। वहीं EWS को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता था।

नोट :

राम वन गमन पथ पुनरवलोकन पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 1 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'राम वन गमन पथ पुनरवलोकन' पुस्तक का अपने निवास कार्यालय में विमोचन किया।

प्रनुख बिंदु

- इस अवसर पर इस पुस्तक के लेखक डॉ. रामगोपाल सोनी तथा प्रकाशक उज्जैन के पुष्कर बाहेती उपस्थित थे। डॉ. सोनी भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
- पुस्तक के लेखक डॉ. रामगोपाल सोनी ने बताया कि इस पुस्तक से जहाँ एक ओर राम वन गमन के वास्तविक पथ का मार्ग प्रशस्त होगा वही प्रमुख संतों के आश्रम और उनके महत्त्व को लोग जान सकेंगे।
- कालांतर में इन क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी यह पुस्तक सहायक होगी।
- यह पुस्तक 11 अध्यायों में विभाजित है जिसमें 316 पृष्ठ हैं। इस पुस्तक में विभिन्न आश्रमों का भी वर्णन किया गया है।
- इस पुस्तक में विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के वन गमन, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से अमरकंटक, अमरकंटक से दंडकारण्य, पंचवटी से किष्किंधा, प्रवर्षण पर्वत से लंका की ओर प्रस्थान, सेतु बंध तथा लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन का विस्तृत उल्लेख है।

राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज

चर्चा में क्यों ?

- 1 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा।

प्रनुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी का प्रस्ताव भेजा है। इस रेंज के बन जाने पर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा।
- खेल मंत्री ने कहा कि शूटिंग के लिये पूरे प्रदेश में दोबारा टैलेंट सर्च किया जाएगा। सिर्फ भोपाल, इंदौर के बच्चों को ही नहीं, सुदूर इलाकों से भी नई प्रतिभाओं को खोजा और तैयार किया जाएगा।
- उन्होंने प्रशिक्षकों को प्रत्येक खिलाड़ी के खेल के सकारात्मक और कमजोर पक्ष की लगातार मॉनीटरिंग करने तथा प्रशासनिक और व्यवस्थाओं में कमी होने पर खेल संचालक को अवगत कराने का निर्देश दिया।
- खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सलालम विधा की समीक्षा के दौरान कहा कि ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में ऑर्टिफिशियल सलालम कोर्स विकसित किया जाएगा।

विद्युत कार्मिकों की पेंशन योजना में कंपनी के मासिक अंशदान में हुई वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

- 1 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत 1 जनवरी, 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिये कंपनी द्वारा मासिक अंशदान, वेतन और महँगाई भत्ते की राशि का 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह आदेश 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावशील होगा। कार्मिकों द्वारा देय मासिक अंशदान वेतन और महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत यथावत् रहेगा।
- बढ़ी दर से कंपनी अंशदान की राशि माह फरवरी 2022 के वेतन भुगतान के साथ जमा होना शुरू होगी।
- 1 अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि के कंपनी अंशदान की बकाया राशि को मार्च एवं अप्रैल 2022 में दो समान किस्तों में जमा किया जाएगा।

रामसर साइट भोज वेटलैंड में शीतकालीन पक्षी गणना हुई पूर्ण

चर्चा में क्यों ?

- 2 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने विश्व वेटलैंड दिवस को मध्य प्रदेश की रामसर साइट भोज वेटलैंड में पिछले 45 दिनों से चल रही पक्षी-गणना का समापन किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य वेटलैंड भोपाल बर्ड्स, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और वीएनएस नेचर सेवियर्स के संयुत्त तत्वावधान में आठ चरणों में हुई पक्षी गणना में देश के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों के वरिष्ठ वन अधिकारी, पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी वैज्ञानिक, फोटोग्राफर्स, विद्यार्थी और पक्षी प्रेमी शामिल हुए।
- भोज वेटलैंड में हुई शरदकालीन पक्षी गणना में 207 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई। इस बार भोपाल के वन विहार में प्रवासी पक्षियों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आने वाले दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं।
- प्रवासी पक्षियों में बार हेडेड गीज, ग्रे लेग गीज, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजन, नॉर्दन शोवलर, कॉमन कूट, कॉम्ब्ब डक, रडी शेल्डक, कॉमन टील, लिटिल ग्रीब, स्पॉट बिल्ड डक, कॉटन टील, ग्रे हेडेड लैपविंग, कॉमन स्नाइप, रेड नेप्ड आइबिस, ग्लॉसी आइबिस, ब्लैक हेडेड आइबिस, पेंटेड स्टोर्क, ओपन बिल स्टोर्क, ब्लू थ्रोट, यूरेशियन राइनेक, ब्लैक रेड स्टार्ट, ब्लैक बिटर्न, चेस्टनट बिटर्न, लॉन्ग टेल्ड मिनिवेट, बूटेड वार्बलर, एशियन ब्राउन फ्लाईकैचर, ब्लैक हेडेड बंटिंग, रेड हेडेड बंटिंग, ब्राउन हेडेड गल, पलाश गल आदि की पहचान की गई।
- वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सहायक संचालक ए.के.जैन ने बताया कि गणना के लिये भोज वेटलैंड को 5 जोन में बाँटा गया- विशनखेड़ी से बीलखेड़ा, बम्होरी, छोटे तालाब से बैरागढ़, बोरखन तथा नीलबड़ से खजुरी। भोज वेटलैंड के किनारे स्थित वन विहार में इस बार दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षी ग्रे लेग गीज, बार हेडेड गीज, ब्लैक बिटर्न, चेस्टनट बिटर्न, ग्रे हेडेड लेप विंग, पेरे ग्रीन फाल्कन और लॉन्ग टेल्ड मिनी वेट पक्षी भी उन्मुक्त विचरण करते हुए दिखे।

डिजिटल ट्रांजेक्शन : देश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अव्वल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ने दिसंबर 2021 में कुल ट्रांजेक्शन में से 91.13 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन के रूप में दर्ज करते हुए देश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों में पहला स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के बाद गवर्नमेंट ऑफ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दूसरे तथा मेसर्स टाटा पावर मुंबई तीसरे स्थान पर रही हैं।
- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में दर्ज हुए आँकड़ों के अनुसार कुल 24,78,282 ट्रांजेक्शन में से 22,58,460 ट्रांजेक्शन डिजिटल माध्यम से किये गए। कंपनी द्वारा दिसंबर माह में संग्रहित की गई कुल राजस्व राशि 519.11 करोड़ रुपए में से 390.45 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल माध्यमों से जमा किये गए हैं।

नोट :

- मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा बिजली बिलों के भुगतान के लिये विभिन्न पेमेन्ट गेटवे को अधिकृत किया गया है। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेन्ट वालेट्स, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से सुरक्षित एवं आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के तीन स्थानों के नाम परिवर्तन को केंद्र की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के तीन स्थानों- होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम परिवर्तन करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

प्रनुख बिंदु

- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होशंगाबाद का नाम 'नर्मदापुरम', शिवपुरी का 'कुंडेश्वर धाम' और बाबई का 'माखन नगर' किये जाने का प्रस्ताव वर्ष 2021 में केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
- गौरतलब है कि रेलवे स्टेशनों, गाँवों, कस्बों और शहरों का नाम बदलने के लिये राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।
- नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित होशंगाबाद का नाम मालवा के शासक होशंगशाह के नाम पर रखा गया था, जबकि बाबई भारतीय काव्य के प्रख्यात छायावादी रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थान है।

मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिन्दी में पढ़ाने की तैयारी प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

- 3 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिन्दी में किये जाने के परिपालन में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

प्रनुख बिंदु

- प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिन्दी में पढ़ाए जाने की कार्यवाही के अनुक्रम में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से इसकी शुरुआत की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिन्दी में किये जाने की घोषणा की गई थी।
- इस कार्यवाही के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य होगा, जहाँ चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं अध्यापन हिन्दी में होगा।
- प्रथम चरण में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय चिकित्सा शिक्षकों द्वारा हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही प्रथम वर्ष के चिकित्सा छात्रों की स्टडी कर आकलन किया जाएगा। पहले हिन्दी पृष्ठभूमि के छात्रों का 2 माह अंग्रेजी माध्यम से एवं 2 माह हिन्दी भाषा के उपयोग से पठन-पाठन का आकलन भी किया जाएगा।
- द्वितीय चरण में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 3 विषयों (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायो-केमिस्ट्री) की पूरक संदर्भ पुस्तकों को हिन्दी भाषा में तैयार किया जाएगा। इस कार्य-योजना को पूरा करने के लिये 3 समिति बनाई गई हैं।
- चिकित्सा पाठ्यक्रम में हिन्दी के उपयोग एवं हिन्दी में पूरक संदर्भ पुस्तकों को तैयार करने की कार्य-योजना बनाने के लिये समिति गठित की गई है। कार्य-योजना को मूर्त रूप देने के लिये अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। इससे इस प्रकल्प का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
- एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायो-केमिस्ट्री की हिन्दी में पूरक संदर्भ पुस्तकें तैयार करने के लिये उप समिति गठित की गई है।
- द्वितीय उप समिति द्वारा हिन्दी में तैयार किये गए विषय को पुन: सूक्ष्म रूप से परिष्कृत करने के लिये एक सत्यापन उप समिति भी गठित की गई है।

राज्य सरकार इस वर्ष से 'मध्य प्रदेश रत्न', 'मध्य प्रदेश गौरव' और 'मध्य प्रदेश श्री' पुरस्कार प्रारंभ करेगी

चर्चा में क्यों ?

- 4 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष से 'मध्य प्रदेश रत्न', 'मध्य प्रदेश गौरव' और 'मध्य प्रदेश श्री' पुरस्कार प्रारंभ करेगी। इस वर्ष ये पुरस्कार नवंबर माह में प्रदान किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- ये पुरस्कार कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री चौहान ने ये बातें अपने निवास पर इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिये चयनित एवं गत वर्षों में पद्म सम्मान प्राप्त कर चुकीं प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित करते हुए कही।
- मुख्यमंत्री ने इस वर्ष पद्म सम्मान प्राप्त करने वाली प्रदेश की विभूतियों- स्व. डॉ. एन.पी. मिश्रा (उनके पुत्र सुनील मिश्रा), दुर्गाबाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे एवं पं. रामसहाय पांडे के साथ ही गत वर्षों में पद्म सम्मान से सम्मानित मध्य प्रदेश की विभूतियों भज्जू श्याम, विजय दत्त श्रीधर, कपिल तिवारी एवं भूरीबाई को भी सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि स्व. डॉ. एन.पी. मिश्रा ने चिकित्सा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। भज्जू श्याम एवं दुर्गाबाई व्याम गोंडी चित्रकला के क्षेत्र में विशिष्ट नाम हैं। प्रकृति एवं लोक-कलाओं पर आधारित इनके चित्र अत्यंत विशिष्ट हैं।
- अर्जुन सिंह धुर्वे का जनजातीय संस्कृति को विशेष पहचान दिलाने में अमूल्य योगदान है। रामसहाय पांडे ने राई नृत्य को दुनिया में नया स्वरूप एवं सम्मान दिया है।
- पत्रकारिता एवं लेखन के क्षेत्र में विजयदत्त श्रीधर देश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने सप्रे संग्रहालय की स्थापना की है। कपिल तिवारी ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और विकास में अमूल्य योगदान दिया है।

स्टार्टअप एक्सपो-2022

चर्चा में क्यों ?

- 5-6 फरवरी, 2022 को मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनिट भोपाल के इंटरप्रेन्योरशिप सेल द्वारा दो दिवसीय स्टार्टअप एक्सपो-2022 का आयोजन किया गया। इस एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।

प्रमुख बिंदु

- इस एक्सपो के माध्यम से 17 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिये दिशा-दर्शन देने का कार्य किया गया। मैनिट के विद्यार्थियों, देश-विदेश के उद्यमियों, निवेशकों और प्रमोटर्स को जोड़ने के लिये इंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा है मध्य प्रदेश शीघ्र ही नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करेगा। इसके अलावा ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट के विचार को भी ज़मीन पर उतारा जाएगा। इस वर्ष मध्य प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप में से कम से कम दो स्टार्टअप को यूनिकार्न स्टार्टअप का दर्जा दिलाने के प्रयास किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि एक बिलियन डॉलर से अधिक मार्केट वैल्यू से यूनिकार्न बनते हैं। देश में इस समय 80 से अधिक यूनिकार्न बन गए हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत में डेकाकार्न कंपनियाँ भी स्थापित होने लगी हैं। डेकाकार्न 10 बिलियन डॉलर से अधिक की मार्केट वैल्यू से संभव होता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 1800 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इसमें से 40 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं ने स्थापित किये हैं।

नोट :

प्रोजेक्ट मीराई का वर्चुअली शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 5 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने 'प्रोजेक्ट मीराई' का वर्चुअली शुभारंभ किया।

प्रनुख बिंदु

- नीमच ज़िले के जावद विकासखंड के 20 हायर सेकंडरी शालाओं के 60 विद्यार्थियों का चयन 'प्रोजेक्ट मीराई' में जापानी भाषा सीखने के लिये हुआ है।
- 'प्रोजेक्ट मीराई' में जावद विकासखंड के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया था जिनका कौशल परीक्षण इन्फोसिस द्वारा ऑनलाइन किया गया।
- परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिन्हें 7 फरवरी से जावद विकासखंड के दो क्लस्टर में प्रतिदिन 2 घंटे का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण देकर जापानी भाषा का कोर्स करवाया जाएगा।
- इस कोर्स के बाद विद्यार्थियों को स्नातक के लिये जापान जाने का अवसर प्राप्त होगा जहाँ ये विद्यार्थी स्नातक करने के साथ ही रोज़गार भी प्राप्त करेंगे।
- ज्ञातव्य है कि 'प्रोजेक्ट मीराई' इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड एवं निर्माण संगठन के सहयोग से जावद क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है।
- 'प्रोजेक्ट मीराई' का उद्देश्य नीमच ज़िले के इच्छुक छात्रों को जापानी भाषा में प्रशिक्षण देकर और उन्हें जापान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिये प्रोत्साहित कर इंडो-जापानी उद्यमियों का पोषण करना है।

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

- 7 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय के साथ ही उनकी मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की।

प्रनुख बिंदु

- इस अकादमी में बच्चों को संगीत की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जबकि संग्रहालय में उनके सभी गाने संग्रहीत किये जाएंगे। वहीं उनकी जयंती पर लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
- गौरतलब है कि लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर, 1929 को हुआ था। कोविड से जुड़ी जटिलताओं के 6 फरवरी, 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई थी।
- संगीत के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण तथा 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था।

राज्य शासन द्वारा 4 नई नगर परिषदें गठित

चर्चा में क्यों ?

- 8 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि स्थानीय लोगों की माँग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा 4 नई नगर परिषदों का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- अनूपपुर ज़िले में नगर परिषद बरगवाँ (अमलाई), सिंगरौली ज़िले में सरई और बरगवाँ तथा सागर ज़िले में कर्रापुर नगर परिषद का गठन किया गया है।
- सागर ज़िले की नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा की सीमा में वृद्धि की गई है। इसमें ग्राम पंचायत मगरधा के अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा, ग्राम पंचायत बेलई के ग्राम भौरदहार, मझगुवाँ, ग्राम पंचायत संजरा के ग्राम रनगुवाँ, ग्राम पंचायत बसारी के ग्राम बसारी और ग्राम पंचायत बरखेरा गौतम के ग्राम हिनौता को शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 9 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में दो नवीन औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के संबंध में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 तथा मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 20 को इन नियमों से निरसित किया गया है।
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 को पूर्णतः निरसित करते हुए नवीन प्रस्तावित मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2021 को अनुमोदित किया गया।
- इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2021 में अन्य तकनीकी सुधार किये गए हैं। इन सुधारों से प्रदेश में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा एवं उपरोक्त नियमों में एकजाई प्रावधान होने से प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता एवं सुगमता हो सकेगी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 412 (407 नगरीय निकायों और 5 छावनी परिषद) नगरीय निकायों को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊँची बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत राशि 2141.85 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण-2 के लिये 551.20 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा। परियोजना का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ड्रिप-2 हेतु 70:30 (विश्व बैंक: राज्य सरकार) के अनुपात में किया जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में दो नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल (बगरौदा गोकलाकुंडी) एवं सीहोर (बढ़ियाखेड़ी) में 59 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से विकसित किये जाने का निर्णय लिया।
- मंत्रिपरिषद ने चार नवीन निजी विश्वविद्यालयों- प्रेस्टीज विश्वविद्यालय (इंदौर), टाइम्स विश्वविद्यालय, (भोपाल), डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय (शिवपुरी) एवं एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय (इंदौर) की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश, 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अध्यादेश जारी करने के लिये आनुषंगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाएँ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

- 9 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने मंत्रालय में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं मेरिट पुरस्कार-2021 प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया।
- सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) का प्रथम पुरस्कार आदिम-जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गोगावां, ज़िला खरगौन को दिया गया और द्वितीय पुरस्कार सेवा सहकारी समिति मर्यादित जामसावली, ज़िला छिंदवाड़ा को दिया गया।
- सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक समिति (क्रेडिट) में प्रथम पुरस्कार सद्गुरु साख सहकारी संस्था मर्यादित ज़िला धार को दिया गया और द्वितीय पुरस्कार गुजराती रामी माली समाज नवयुवक साख सहकारी संस्था मर्यादित नौगाँव, ज़िला धार को दिया गया।
- सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक समिति (प्र-संस्करण) के क्षेत्र में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, रेहटी, ज़िला सीहोर को और सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति (महिला) में इंदौर ज़िले की स्वश्रयी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित को प्रथम पुरस्कार दिया गया।

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिये प्रदेश के छः अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- 10 फरवरी, 2022 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिये मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के छः अधिकारियों को राष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- नीपा ने इस सम्मान के लिये मध्य प्रदेश से सर्व शिक्षा अभियान के तत्कालीन डीपीसी गोपाल सिंह बघेल (सिवनी), तत्कालीन डीपीसी आर.एस. तिवारी (हरदा), तत्कालीन डीपीसी कमल कुमार नागर (राजगढ़), शोएब खान बीआरसीसी (मंदसौर), रामानुज शर्मा बीईओ/बीआरसीसी (अलीराजपुर) और प्रवीण चंद्र उपाध्याय बीआरसीसी (मंडला) का चयन किया है।
- इन सभी अधिकारीयों को नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने डिजिटल प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये।

ग्वालियर में बेबी फीडिंग सेंटर शुरू

चर्चा में क्यों?

- 10 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी और कुलसचिव डॉ. सुशील मंडेरिया ने विश्वविद्यालय में पहला बेबी फीडिंग सेंटर 'दुलार' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- जीवाजी विश्वविद्यालय यह अनूठी शुरुआत करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है।
- कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान आने वाली माँ और बच्चे की संवेदनाओं को समझ कर इस फीडिंग सेंटर को परीक्षा भवन में ही बनाने का निर्देश दिया गया है।
- इस फीडिंग सेंटर का नाम 'दुलार' रखा गया है।

नोट :

इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट (आईडीपी) पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

चर्चा में क्यों?

- 10 फरवरी, 2022 को भोपाल में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 'इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन'पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में किया गया।

प्रनुख बिंदु

- इस कार्यशाला में तीन तकनीकी सत्र हुए। पहले सत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये संस्थागत विकास योजना की अवधारणा और आवश्यकता पर चर्चा हुई, दूसरा सत्र संस्थान परिसर डिज़ाइन और स्पेस प्लानिंग पर आधारित रहा तथा तीसरे सत्र में एक आदर्श आईडीपी की अनिवार्यताओं पर चर्चा हुई।
- इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है। यह आईडीपी शिक्षा का विज़न डॉक्यूमेंट है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) की रूपरेखा तैयार की है। इससे शिक्षण संस्थान अपने लक्ष्यों और बुनियादी ढाँचे को बेहतर बना सकते हैं। आईडीपी उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी।
- संस्थागत विकास योजना का मूल उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाकर विद्यार्थियों को एक सफल नागरिक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को संस्थागत विकास योजना तैयार करना अनिवार्य होगा।
- उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिये संस्थागत विकास योजना पर देश में पहली बार इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है।

मध्य प्रदेश में मिले डायनासोर के अंडे

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के सेंधवा विकासखंड की वरला तहसील के जंगल में डायनासोर के अंडों से संबंधित जीवाश्म मिले हैं।

प्रनुख बिंदु

- बड़वानी के जंगल में मिली 10 अंडाकार चटानों की जाँच के पश्चात् पुरातत्त्वविद् डॉ. डीपी पांडे ने बताया कि ये डायनासोर के अंडे हैं, जो 60 लाख से 1 करोड़ वर्ष पुराने हो सकते हैं।
- इन अंडों में सबसे बड़े अंडे का वज़न करीब 40 किलो है, जबकि अन्य करीब 25 किलो तक के हैं। इनमें से 3 अंडों को इंदौर स्थित संग्रहालय में रखा जाएगा।
- धार ज़िले में 2007 में भी डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, जिन्हें मांडू में बने फॉसिल पार्क में रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि घुघुवा जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडौरी ज़िले में शाहपुरा के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 18 जीव वैज्ञानिक कुलों के 31 वंशों के पौधों के जीवाश्म (फॉसिल) मिले हैं।

नोट :

भारत भवन की 40वीं वर्षगाँठ समारोह का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 13 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने भारत भवन की 40वीं वर्षगाँठ पर विविध कला समारोह का शुभारंभ किया।

प्रनुख बिंदु

- मंत्री उषा ठाकुर ने भारत भवन मुक्ताकाश मंच पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राज्य शिखर सम्मान के लिये विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों साहित्यकारों और रंगकर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही पद्मश्री के लिये चयनित दुर्गा बाई व्याम के चित्रों, रेखांकन कला प्रदर्शनी-सुरेखा और प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया।
- रूपंकर कलाएँ के लिये राष्ट्रीय कालिदास सम्मान गुजरात के ज्योति भटे को वर्ष 2017 के लिये, नई दिल्ली की इरा चौधरी को 2018 के लिये, नई दिल्ली के परमजीत सिंह को 2019 के लिये और बड़ौदा के ध्रुव मिस्त्री को वर्ष 2020 के लिये दिया गया।
- रंगकर्म के लिये राष्ट्रीय कालिदास सम्मान लखनऊ के डॉ. अनिल रस्तोगी को वर्ष 2019 के लिये और मुंबई के वामन केंद्रे को वर्ष 2020 के लिये प्रदान किया गया।
- वर्ष 2019 एवं 2020 के लिये विभिन्न विषयों में निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य शिखर सम्मान प्रदान किया गया-

विषय	वर्ष 2019	वर्ष 2020
हिंदी साहित्य	शैवाल सत्यार्थी (ग्वालियर)	हरी जोशी (भोपाल)
उर्दू साहित्य	नईम कौसर (भोपाल)	देवीशरण (भोपाल)
संस्कृत साहित्य	डॉ. रामेश्वर प्रसाद गुप्ता (दतिया)	प्रो. रहस बिहारी द्विवेदी (जबलपुर)
शास्त्रीय संगीत	पं. प्रभाकर लक्ष्मण गोहदकर (ग्वालियर)	पं. सज्जनलाल ब्रह्माभटे (भोपाल)
रूपंकर कलाओं	देवी लाल पाटीदार (भोपाल)	मनीष पुष्कले (नई दिल्ली)
नाटक	वैशाली गुप्ता (भोपाल)	के.जी. त्रिवेदी (भोपाल)
जनजातीय एवं लोक कलाओं	अग्नेश केरकटेा (भोपाल)	पूर्णिमा चतुर्वेदी
दुर्लभ वाद्य वादन	बाबूलाल भोला (सागर)	डॉ. वर्षा अग्रवाल (उज्जैन)

- इस समारोह के पहले दिन संतोष संत के निर्देशन में स्वर वेणु गुरुकुल इंदौर के कलाकारों ने बाँसुरी सप्तक की मधुर संगीतमयी प्रस्तुति दी।
- इस पाँच दिवसीय समारोह में 13 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक बहुकला केंद्र भारत भवन में सुगम संगीत, आकर्षक नृत्य, स्लाइड शो, नृत्य नाटिका और कविता पाठ जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी।

विंध्य एवं महाकौशल क्षेत्र को मिली नई ट्रेनों की सौगात

चर्चा में क्यों ?

- 12 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश को कई नई ट्रेनों की सौगात दी। साथ ही रानी कमलापति स्टेशन से राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रनुख बिंदु

- नई संचालित ट्रेनों में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन नं. 02195 रानी कमलापति- रीवा, ट्रेन नं. 02196 रीवा-रानी कमलापति साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन एवं ट्रेन नं 05713 जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं।
- इन ट्रेनों के संचालन से मध्य प्रदेश के विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

नोट :

- रीवा-रानी कमलापति साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन कमलापति स्टेशन से रीवा तक 9 स्टेशनों को कवर करेगी।
- इन नई ट्रेन सेवाओं को आरंभ करने से सतना, मैहर, कटनी, मुढवारा, दमोह, सागर, बीना, विदिशा क्षेत्रों का उत्तरोतर विकास होगा एवं इन क्षेत्रों की जनता, विद्यार्थी, व्यापार एवं पर्यटन को लाभ होगा।
- वहीं यात्रियों की सुगम रेल यात्रा के लिये जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर ट्रेन को बहाल किया गया है। जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर ट्रेन कुल 19 स्टेशनों को कवर करेगी।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय में स्थापित होगा 'सामुदायिक रेडियो कर्मवीर'

चर्चा में क्यों ?

- 13 फरवरी, 2022 को विश्व रेडियो दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो केजी सुरेश ने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (भोपाल) के विशनखेड़ी स्थित नवनिर्मित परिसर में केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की स्थापना के लिये नियति पत्र प्रदान किया है।

प्रनुख बिंदु

- विश्वविद्यालय की ओर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिये आवश्यक प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
- ज्ञातव्य है कि सामुदायिक रेडियो आंदोलन भारत में 1995 के समय शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने वायु तरंगों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया।
- प्रत्येक सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपने-अपने समुदाय की भाषाओं को प्राथमिकता देती है, जो भाषा आम टी.वी. चैनलों में अथवा अखबारों में नहीं मिलती वह सामुदायिक रेडियो स्टेशन में मिलती है।
- एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना प्रसारण 15 कि.मी. के रेडियस में कर सकता है।
- विश्व रेडियो दिवस-2022 की थीम- 'रेडियो और विश्वास' है।
- उल्लेखनीय है कि 3 नवंबर, 2011 को यूनेस्को के 36वें सत्र ने विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाने की घोषणा की, क्योंकि 13 फरवरी, 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यू.एन. रेडियो की स्थापना की थी।

पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने लागू किया पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

- 14 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित सभी जानकारी सर्व संबंधितों को एक ही पटल पर उपलब्ध कराने एवं उसकी समीक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

प्रनुख बिंदु

- पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से अब पेंशन प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंपनी द्वारा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आटोमेटिक बनाया गया है।
- कंपनी से सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर पेंशन आदेश (पीओ), पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- इस प्रणाली में प्रस्तुत किये गए आवेदन के अनुमोदन एवं आदेश जारी होने की सूचना संबंधित पेंशनर को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
- पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिये अलग से पोर्टल pms.mpez.co.in बनाया गया है। इस पर लॉगिन कर पेंशन प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

नोट :

मध्य प्रदेश के मोहम्मद अरशद खान आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम में शामिल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बंगलुरु में आयोजित आईपीएल, 2022 के 15वें सीजन की मेगा ऑक्शन में मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के गोपालगंज गाँव निवासी आलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अरशद खान आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा बन गए हैं।

प्रनुख बिंदु

- मुंबई इंडियंस ने मोहम्मद अरशद खान को बेस प्राइस 20 लाख रुपए में अपने टीम में शामिल किया है।
- इसी वर्ष अरशद खान मध्य प्रदेश की रणजी टीम में शामिल हुए हैं।
- उन्होंने ज़िला स्तर पर क्रिकेट खेलने की शुरुआत वर्ष 2006 से की थी। वर्ष 2012 में वह मध्य प्रदेश की अंडर-16 टीम का हिस्सा बने। इसके बाद 2015 में अंडर-19 टीम में शामिल हुए। वर्ष 2017-18 में वह अंडर-23 टीम का हिस्सा बने।
- अरशद ने वर्ष 2020 में बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर-23 वीके नायडू स्पर्धा में 10 मैचों में 36 विकेट लिये तथा 400 रन भी बनाए। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2020 में ही विजय हजारे ट्रॉफी व सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था।

इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर के लिये पेटेंट प्राप्त हुआ है।

प्रनुख बिंदु

- हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर (HEMT) सामान्यत: एक ऑफ उपकरण (OFF device) है, जो 4 एंपियर तक की विद्युत-धारा को परिवर्तित कर सकता है और 600 वोल्ट पर संचालित हो सकता है। HEMT को एकीकृत सर्किट में डिजिटल ऑन-ऑफ स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है।
- HEMT ट्रांजिस्टर, सामान्य ट्रांजिस्टर की तुलना में मिलीमीटर तरंग आवृत्तियों तक की उच्च आवृत्तियों पर काम करने में सक्षम होते हैं।
- इसके निम्नलिखित लाभ होंगे-
  - 5G और 6G तकनीकी से संबंधित उपकरणों में
  - आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने में
  - कम क्षमता वाले एंपलीफायरों और रक्षा उद्योग में
  - उच्च आवृत्ति वाले उत्पादों, जैसे- सेलफोन, सैटेलाइट टेलीविज़न रिसीवर, वोल्टेज कन्वर्टर्स और रडार उपकरणों में

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 15 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया।

प्रनुख बिंदु

- इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉलोनाइजर्स अब एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। साथ ही 30 दिन की समय-सीमा में संबधित प्रमाण-पत्र जारी किये जाएँगे।

- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेज़ी आएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किये हैं।
- आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं वाट्सएप के ज़रिये आवेदक को सूचना, वाट्सएप के ज़रिये सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने की सुविधा और संचालनालय के लिये मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी।
- कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिये मान्य होंगे।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना (उतर प्रदेश-मध्य प्रदेश) को लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक संचालन समिति एवं केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया गया है।

प्रनुख बिंदु

- इस 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे।
- संचालन समिति समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, केबीएलपीए के लिये मौलिक प्रशासनिक नीतियों, उपनियमों और मानदंडों को मंज़ूरी देगी, अपने वार्षिक बजट, वित्तीय विवरणों को मंज़ूरी देने और जाँचने के अलावा अपने दायित्वों एवं ऋण संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
- सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण दौधन बांध, बिजली घर, केन-बेतवा लिंक जल वाहक नहर, सुरंग, लोअर परियोजना, कोठा बैराज तथा बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के निष्पादन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- केबीएलपीए का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 ज़िले- पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाँदा, महोबा, झाँसी और ललितपुर ज़िले हैं।
- इस पूरी योजना से इन सभी ज़िलों की करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनाया जाएगा।

भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज

चर्चा में क्यों ?

- 16 फरवरी, 2022 को संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने कई कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा की।

प्रनुख बिंदु

- भोपाल में स्थापित होने वाले ग्लोबल स्किल पार्क में युवा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर हो सकेगें।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को रोज़गार देने के लिये संत रविदास स्व-रोज़गार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना तथा वित्त पोषण योजना आरंभ करने की घोषणा की।

नोट :

- मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और ज़िला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- संत रविदास (रैदास) का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा को हुआ था। इसलिये प्रतिवर्ष माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास की जयंती मनाई जाती है।
- इनके पिता का नाम रग्घु तथा माता का नाम घुरविनिया था जबकि पत्नी का नाम लोना बताया जाता है।
- इनके माता-पिता एक चर्मकार थे। आजीविका के लिये अपने पैतृक कार्य को अपनाने के बावजूद ये हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहे।
- कबीर के बाद रविदास संत रामानंद के शिष्यों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए।
- इनके पद्य सिक्खों के पवित्र ग्रंथ 'गुरुग्रंथ साहिब'में संगृहीत हैं।
- संत रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रम के महत्त्व, समानता, असहायों की सेवा के लिये जन-जन को प्रेरित किया।
- मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोज़गार के लिये विशेष पहल की गई है। संत रविदास स्व-रोज़गार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिये 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिये भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोज़गार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिये दो करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिये एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।

MPPSC परीक्षा में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है।

प्रनुख बिंदु

- हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिये हैं। साथ ही 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है।
- याचिका में कहा गया कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से कुल आरक्षण 63 प्रतिशत हो जायेगा। जो कि इंदिरा साहनी वाद में दिये गए आदेश का उल्लंघन है।
- गौरतलब है कि सामान्य वर्ग की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें एमपीपीएससी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को जारी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी थी।
- मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2021 में राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिये विद्यार्थियों के 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था।
- सरकार द्वारा ओबीसी को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पहले की तरह 14 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के लिये मार्च 2019 में अंतरिम आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी के द्वारा विभिन्न पदों की परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का अंतरिम आदेश दिया था।

नोट :

- इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने चार अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, एनएचएम भर्ती और महिला आरक्षण के संबंध में भी याचिकाएँ दायर की गई थीं। इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को एमपीपीएससी का परीक्षा परिणाम 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ जारी कर दिया था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ ने 6 नए जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इन नए जजों में 3 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और 3 न्यायिक अधिकारी हैं।
- अधिवक्ता वर्ग में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह बर्टी, ग्वालियर के अधिवक्ता डीडी बंसल और इंदौर के अधिवक्ता मिलिंद रमेश फड़के को हाईकोर्ट में जज बनाया गया हैं।
- वहीं न्यायिक अधिकारी वर्ग में उज्जैन के प्रधान ज़िला जज प्रकाश चंद्र गुप्ता, इंदौर के न्यायिक अधिकारी दिनेश कुमार पालीवाल और बालाघाट के ज़िला जज अमरनाथ केसरवानी को हाईकोर्ट जज बनाया गया है।
- विदित है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 53 है, लेकिन वर्तमान में 29 जज कार्यरत् थे, 6 नए जजों की नियुक्ति के बाद एमपी हाईकोर्ट में कार्यरत् जजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई।
- हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने से मुकदमों के निराकरण में तेज़ी आएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

- 18 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खंडों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिये फीडर रूट्स (Feeder Routes) के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
- इसके साथ ही नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्तपोषण एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से प्रारंभ होकर डिंडोरी-जबलपुर-औबेदुल्लागंज-बुधनी-नसरुल्लागंज-संदलपुर-करनावद-इंदौर-धार-सरदारपुर-झाबुआ (मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा) तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 906 कि.मी. है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्वनिर्मित 17 मार्गों पर अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से पाँच वर्ष तक उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण को स्वीकृति प्रदान की गई।

नोट :

- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधा एवं सहायता और फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है।
- मंत्रिपरिषद ने 19वें एशियन गेम्स 2022 (चीन) की तैयारी के लिये घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये अनुमानित व्यय राशि 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी।
- मंत्रिपरिषद ने 'मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल' का नाम बदल कर 'मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड' करने और इससे संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने की स्वीकृति दी।

जल जीवन मिशन में कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के लिये 45 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

- 18 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं के लिये आई.एस.ए. की नियुक्ति हेतु 44 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

प्रनुख बिंदु

- जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) का चयन किया जाता है। यह एजेंसी जल-प्रदाय योजना क्षेत्र में पेयजल और सामुदायिक प्रबंधक, जल गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण, जल संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जल के लिये अपनी सेवाएँ देगी।
- मध्य प्रदेश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने के लिये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य किये जा रहे हैं।
- जल जीवन मिशन में प्रदेश के 13 ज़िलों- क्रमश: भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के 10 हज़ार 261 ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के लिये आई.एस.ए. की नियुक्ति की गई है। इन्हीं ज़िलों की सेवाओं पर यह राशि व्यय की जा सकेगी।

पर्यटन बोर्ड का साहस संस्था के साथ हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों?

- 20 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल की उपस्थिति में खजुराहो में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म मिशन में पायलट प्रोजेक्ट 'क्लीन डेस्टिनेशन' की लॉन्चिंग की गई। इस परियोजना को संचालित करने के लिये पर्यटन बोर्ड और सहयोगी संस्था 'साहस' के मध्य कर्णावती इंटरप्रिटेशन केंद्र मडला में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रनुख बिंदु

- पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में पन्ना नेशनल पार्क के आस-पास के 30 गाँवों को क्लीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इस परियोजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाएगा। सामुदायिक जागरूकता, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से पर्यटन स्थलों और आस-पास के गाँवों को क्लीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इस अवसर पर ज़िला पर्यटन, संस्कृति एवं पुरातत्त्व परिषद पन्ना के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया।

48वाँ खजुराहो नृत्य समारोह-2022

चर्चा में क्यों ?

- 20 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वाँ 'खजुराहो नृत्य समारोह-2022' का शुभारंभ किया। इस समारोह का आयोजन 26 फरवरी तक किया जाएगा।

प्रनुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 में मंदिर प्रांगण से ही हुई थी। आरंभ के दो-तीन वर्षों बाद ही इसे मंदिर प्रांगण में करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप यह समारोह बाहर मैदान में किया जाने लगा। पिछले वर्ष संस्कृति विभाग की इस कार्यक्रम को मंदिर प्रांगण में कराने की कोशिश को सफलता मिली और इस वर्ष भी यह समारोह मंदिर प्रांगण में ही किया जा रहा है।
- समारोह में इस वर्ष 'महिलाओं के लिये सुरक्षित पर्यटन परियोजना' के बैनर तले 5 किलोमीटर की 'दिल खेल के घूमो' मैराथन भी हुई। इसका उद्देश्य 'हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं' के स्लोगन से पर्यटन स्थलों में महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है।
- संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर ने घोषणा की कि मानव जीवन में नृत्य की महानता और उसके योगदान को देखते हुए खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य संदर्भ का केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- 48वें खजुराहो नृत्य समारोह की प्रस्तुतियों का साक्षी बनने के लिये 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त सपरिवार समारोह में शामिल हुए। इनमें कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रूनेई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओ के राजदूत तथा उच्चायुक्त शामिल हैं।
- समारोह में शास्त्रीय नृत्य के लिये सुनयना हजारी लाल को वर्ष 2019-20 तथा शांता और वी.पी. धनंजयन को वर्ष 2020-21 के लिये राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें 2 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका, शाल और श्रीफल प्रदान किया गया।
- साथ ही समारोह में राज्य रुपंकर कला पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रदान किये गए, जो निम्न हैं-

पुरस्कार	पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता
देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार	बदनावर की प्रिया सिसोदिया (बदनावर)
मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार	स्वपन तरफदार (इंदौर)
सैयद हैदर रजा पुरस्कार	दुर्गेश बिरथरे (जबलपुर)
दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार	नरेंद्र जाटव (अशोकनगर)
जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार	संजय धवले (अशोकनगर)
विष्णु चिंचालकर पुरस्कार	मुनि शर्मा (ग्वालियर)
नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार	अग्नेश केरकेटा (भोपाल)
रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार	ऋतुराज श्रीवास्तव (जबलपुर)
राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार	ज्योति सिंह (सागर)
लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार	डॉ. सोनाली चौहान (पीठवे) (देवास)

- इस नृत्य समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण और ज़िला प्रशासन छतरपुर के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यशैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त है।

नोट :

इंदौर में गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 19 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया।

प्रनुख बिंदु

- इंदौर में गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट बनने से वेस्ट-टू-वेल्थ तथा सर्कुलर इकॉनमी की परिकल्पना साकार हुई है। इससे भारत के स्वच्छता अभियान भाग-2 को नई ताकत मिलेगी, जिसके अंतर्गत आने वाले 2 वर्षों में देश के सभी शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कर ग्रीन ज़ोन बना दिया जाएगा।
- इंदौर के प्लांट से सीएनजी के अलावा 100 टन जैविक खाद भी रोज़ाना प्राप्त होगा। इससे इंदौर शहर में हर रोज करीब-करीब 400 बसें चलाई जा सकेंगी।
- यह प्लांट संपूर्ण एशिया महाद्वीप में जैविक अपशिष्ट से बायो सी.एन.जी का सबसे बड़ा तथा देश का पहला प्लांट है।
- बायो सी.एन.जी प्लांट पी.पी.पी. मॉडल पर आधारित है। इस प्लांट की स्थापना पर जहाँ एक ओर नगर निगम, इंदौर को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्लांट को स्थापित करने वाली एजेंसी IEISL, नई दिल्ली द्वारा नगर निगम, इंदौर को प्रतिवर्ष ढाई करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में दिये जाएंगे।
- इस प्लांट में प्रतिदिन 550 एमटी गीले कचरे (घरेलू जैविक कचरे) को उपचारित किया जाएगा, जिससे 17 हज़ार 500 किलोग्राम बायो सी.एन.जी. गैस तथा 100 टन उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक कम्पोस्ट का उत्पादन होगा।
- इस प्लांट से उत्पन्न होने वाली बायो सी.एन.जी. में से 50 प्रतिशत गैस नगर निगम, इंदौर को लोक परिवहन की संचालित बसों के उपयोग के लिये उपलब्ध होगी, शेष 50 प्रतिशत गैस विभिन्न उद्योग एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को विक्रय की जा सकेगी।
- इंदौर नगर का वेस्ट सेग्रीगेशन उत्तम क्वालिटी का होने से इस प्लांट को इंदौर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्लांट स्थापना के निर्णय के पूर्व उक्त कंपनी ने गीले कचरे के गत एक वर्ष में 200 से अधिक नमूने लेकर परीक्षण करवाया। परीक्षण के परिणाम के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि गीले कचरे में मात्र 0.5 से 0.9 प्रतिशत ही रिजेक्ट उपलब्ध है, जो अन्य यूरोपियन देशों की तुलना में भी उच्च गुणवत्ता का होना पाया गया।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर में झोलाधारी इंदौरी अभियान का आगाज़ भी किया गया है। इंदौर नगरीय क्षेत्र की स्लम बस्तियों को ग्रीन स्लम के रूप में विकसित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट इंदौर के आसपास के ग्राम से पशुपालकों और किसानों से गोबर और अन्य कचरे को क्रय कर धन बनाने वाला संयंत्र होगा। अनेक परिवारों को इस प्लांट से स्थायी रोज़गार मिल रहा है।
- कचरे के साथ गोबर का उपयोग बैक्टीरिया डेवलप करने की प्रोसेसिंग में किया जाएगा। इंदौर में बाज़ार मूल्य से 5 रुपए प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिये सीएनजी की उपलब्धता होगी।
- प्लांट में शुरुआती दौर में 21 प्रतिशत और अगले तीन वर्ष में शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इंदौर शहर को कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा। साथ ही इस प्लांट से आगामी 20 वर्ष तक इंदौर नगर निगम को प्रति वर्ष 2 करोड़ 52 लाख प्रीमियम मिलता रहेगा।

नकली फिंगर प्रिंट की समस्या का समाधान

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में आईआईटी इंदौर और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आईईटी) डीएवीवी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा फिंगर प्रिंट बायोमीट्रिक सिस्टम तैयार किया है, जिससे नकली फिंगर प्रिंट का उपयोग कर होने वाले अपराधों की रोकथाम की जा सकेगी। इस महत्त्वपूर्ण शोध का पेटेंट कराया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस तकनीक की सहायता से बायोमीट्रिक मशीनों में ऐसा सेंसर लगाया जा सकेगा, जो असली और नकली फिंगर प्रिंट की पहचान कर लेगा। व्यक्ति जैसे ही अपनी अंगुली स्कैनर पर रखेगा, सेंसर उसकी पल्स (नाड़ी) भी पढ़ लेगा। इससे किसी मृत व्यक्ति के फिंगर प्रिंट के इस्तेमाल की आशंका भी समाप्त हो जाएगी।
- नकली और असली फिंगर प्रिंट की पहचान करने में सफलता मिलने से आधार और बायोमीट्रिक से जुड़े सभी तरह के उपकरणों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि बैंकिंग क्षेत्र के साथ ही चोरी रोकने के लिये कई दफ्तरों और घरों में बायोमीट्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। कई प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में भी बायोमीट्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। शोध के आधार पर नई बायोमीट्रिक मशीनों का उत्पादन होने के बाद, नकली या मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं हो सकेगा।
- कई बार हैकर्स फिंगरप्रिंट की छवि चुराकर उसका उपयोग आधार, सिम और बैंकिंग क्षेत्रों में करने की कोशिश करते हैं। अभी बायोमीट्रिक मशीनें अंगुली की लकीरों को पढ़ती हैं और आगे की प्रक्रिया के लिये अनुमति दे देती हैं। नई तरह की मशीनों पर अंगुली लगाने के बाद सेंसर ब्लड की सेल्स और पल्स भी पता करेगा।
- शोध पर काम करने वाले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आईईटी) के प्रो. शशि प्रकाश एवं आईआईटी इंदौर के प्रो. विमल भाटिया हैं।

मध्य प्रदेश में इंदौर HIV और एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में पहले नंबर पर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में इंदौर पहले स्थान पर है, अर्थात् यहाँ खतरा सबसे ज़्यादा है।

प्रमुख बिंदु

- दूसरे शहरों के मुकाबले इंदौर में फीमेल सेक्स वर्कर तो ज्यादा हैं ही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ GAY (पुरुषों से संबंध बनाने वाले पुरुष) भी ज्यादा हैं। GAY के मामलों में ग्वालियर दूसरे, जबलपुर तीसरे और भोपाल चौथे नंबर पर है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी राज्य में हाई रिस्क ग्रुप के 55 हज़ार लोगों में HIV और एड्स की रोकथाम के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं के ज़रिये काम कर रही है। सोसाइटी हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को जागरूक करती है तथा HIV स्क्रीनिंग कराने का काम भी करती है, जिनमें HIV की पुष्टि होती है, उनका इलाज कराया जाता है।
- HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के सेक्स पार्टनर और बच्चों की भी HIV स्क्रीनिंग कराई जाती है, ताकि संक्रमण पैलने से रोका जा सके।
- मध्य प्रदेश में हाई रिस्क ग्रुप में करीब 12 हज़ार MSM (Men who have Sex with Men) रिकॉर्ड में हैं। सबसे ज़्यादा 1570 इंदौर ज़िले में दर्ज हैं। ग्वालियर में 849, जबलपुर में 795 और भोपाल में 766, वहीं आगर-मालवा में 8 और सीधी में 2 लोग डैड कैटेगरी के रिकॉर्ड में हैं।
- फीमेल सेक्स वर्कर्स (FSW) के मामले में भी इंदौर पहले नंबर पर है। प्रदेश में करीब 35 हज़ार फीमेल सेक्स वर्कर्स की जानकारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पास दर्ज है। सबसे ज़यादा FSW इंदौर में 2513 में हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा में 2464 हैं।
- प्रदेश में इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र (IDU), यानी इंजेक्शन सिरिंज के ज़रिये नशा करने वाले करीब 8 हज़ार लोग रिकॉर्ड में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा IDU कैटेगरी के लोग जबलपुर ज़िले में 1303 हैं, भोपाल में 1223 और रीवा में 1089 हैं।
- एड्स की रोकथाम के बारे में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के.डी. त्रिपाठी ने बताया कि हाई रिस्क कैटेगरी में अलग-अलग ग्रुप्स तक पहुँचने के लिये करीब 68 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएँ (टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट) चलाई जा रही हैं।
- इन प्रोजेक्ट के ज़रिये हाई रिस्क ग्रुप में HIV की रोकथाम के लिये स्क्रीनिंग, यौन संबंधों के दौरान कंडोम का उपयोग करने, इंजेक्शन से नशा करने वालों को सिरिंज उपलब्ध कराना है।

नोट :

- HIV संक्रमितों को AET सेंटर से लिंक कराकर नियमित दवाएँ और उपचार मुहैया कराने का काम किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश में HIV की स्क्रीनिंग के लिये करीब 1652 FICTC (Facilitated Integrated Counselling and Testing Centre) संचालित हैं।

बटेश्वर के मंदिरों का पुनरुद्धार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में इंफोसिस द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार पुन: प्रारंभ किया गया है।

प्रनुख बिंदु

- गौरतलब है कि बटेश्वर मंदिर समूहों के संरक्षण का कार्य वर्ष 2005 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के तत्कालीन क्षेत्रीय अधीक्षक के.के. मुहम्मद द्वारा शुरू किया गया था।
- 2005 से 2011 के मध्य 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया था।
- ये मंदिर समूह शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित हैं, अर्थात् ये हिंदू धर्म की तीन प्रमुख परंपराओं (शैव, वैष्णव और शाक्त) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मध्य प्रदेश के पुरातत्त्व निदेशालय के अनुसार, गुर्जर-प्रतिहार राजवंश के शासनकाल में 200 मंदिरों का यह समूह बनाया गया था।

‘वैद्य आपके द्वार’ टेलीमेडिसिन ऐप को मिला राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों?

- 22 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन ऐप ‘आयुष क्योर’ को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रनुख बिंदु

- ‘वैद्य आपके द्वार’ योजना में विकसित आयुष क्योर ऐप को प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में विषय-विशेषज्ञों तथा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया। इसे जन-सामान्य में अधिक-से-अधिक प्रचारित करने का सुझाव भी दिया गया है।
- इस ऐप के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आयुष डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। ऐप के द्वारा ही रिपोर्ट भेजने तथा उपचार संबंधी दिशा-निर्देश प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- मध्य प्रदेश में अब तक 37 हज़ार से ज़्यादा यूज़र द्वारा आयुष क्योर ऐप डाउनलोड किया जा चुका है। ऐप पर बुकिंग करने वालों में से 88 प्रतिशत लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है।
- आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई ‘वैद्य आपके द्वार’ योजना के ज़रिये घर-बैठे आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श लिया जा रहा है।
- इस योजना में आयुष की तीनों विधाओं- आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है।
- आयुष विभाग ने सामान्य जन को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर उपलब्ध कराने के मकसद से इस योजना को टेलीमेडिसिन ऐप से उपलब्ध कराया है।

प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना

चर्चा में क्यों?

- 23 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की।

नोट :

प्रनुख बिंदु

- उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।
- मंत्री ने उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागीय अधिकारी को केरल विश्वविद्यालय का दौरा कर कंसेप्ट पेपर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित है।
- कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा से युवा परिचित हुए हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से घर-घर तक शिक्षा की पहुँच आसान होगी। विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

शिवपुरी में खुलेगी देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी

चर्चा में क्यों ?

- 24 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि प्रदेश की युवा क्रिकेट प्रेमी बेटियों के लिये देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में खोली जाएगी।

प्रनुख बिंदु

- यह प्रदेश की 11वीं अकादमी होगी। अब तक मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स, शूटिंग, घुडसवारी, वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट, पुरुष हॉकी, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाज़ी और पुरुष क्रिकेट अकादमी संचालित हैं।
- मध्य प्रदेश राज्य महिला क्रिकेट अकादमी के लिये 28 फरवरी से टैलेंट सर्च प्रारंभ होगा। इसमें 14 से 21 साल की खिलाड़ी शामिल हो सकती हैं। अकादमी के लिये पहला टैलेंट सर्च 28 फरवरी और 1 मार्च को इंदौर में होगा। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी ज़िलों के खिलाड़ी शामिल होंगे।
- भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के ज़िलों के लिये भोपाल में 2 एवं 3 मार्च को टैलेंट सर्च होगा, जबलपुर संभाग के ज़िलों के लिये जबलपुर में 4 एवं 5 मार्च को तथा ग्वालियर एवं चंबल संभाग के ज़िलों के लिये ध्शिवपुरी में 7 एवं 8 मार्च को टैलेंट सर्च होगा।
- खेल विभाग द्वारा सभी अकादमी में चयनित खिलाड़ियों को शिक्षा, आवास, भोजन, प्रशिक्षण किट की सुविधाएँ नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पायलेट प्रोजेक्ट जीएमसी से होगा शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 24 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश में हिन्दी में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में गठित हिन्दी पाठ्यक्रम उच्च समिति की बैठक में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हिन्दी में एमबीबीएस की पढ़ाई की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत गांधी मेडिकल कॉलेज से होगी।

प्रनुख बिंदु

- मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि हिन्दी प्रकोष्ठ का विधिवत् गठन कर सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- समानांतर रूप से हिन्दी माध्यम से पढ़े छात्रों को सहायता के तौर पर यह व्यवस्था की जा रही है। अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी की पुस्तकें भी उपलब्ध कराने की तैयारी है।
- नवाचार के रूप में प्रथम वर्ष के 3 विषयों की पुस्तकों का रूपांतरण व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। देवनागरी का उपयोग कर विद्यार्थियों को टूल और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मंत्री सारंग ने कहा कि पुस्तकों का वॉल्यूम क्रमबद्ध होगा। सब वॉल्यूम बनाकर अप्रैल-मई में पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कॉपीराइट का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी को भी हिन्दी में विद्यार्थियों को समझाते हुए क्लासेज़ लेने के निर्देश दिये गए हैं। तीन विषयों के लिये तीन वार-रूम बनाए जा रहे हैं।
- भोपाल में एनाटॉमी और बायो-केमेस्ट्री तथा इंदौर में फिजियोलॉजी का वार-रूम तैयार किया जाएगा। इसमें विषय के रूपांतरण के सत्यापन की जाँच होगी।
- विद्यार्थियों की सुविधा के लिये हिन्दी लेक्चर के ऑडियो-वीडियो बनाकर यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसने इस नवाचार की शुरुआत की और आगे भी लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी रहेगा।

‘हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणास्त्रोत’ पुस्तिका का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 25 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने संस्था ‘पीपल’के सहयोग से तैयार की गई पुस्तिका ‘हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणास्त्रोत’के तीसरे और चौथे संस्करण का वर्चुअल लोकार्पण केंद्र के एडुसेट वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष से किया।

प्रनुख बिंदु

- दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर आधारित शिक्षकों को प्राप्त नवीन शैक्षिक जानकारियों, अकादमिक अनुभवों और विचारों को अन्य शिक्षकों से साझा करने एवं उनके प्रयासों को प्रेरित करने के लिये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सहयोगी संस्था ‘पीपल’के सहयोग से यह पुस्तिका तैयार की गई है।
- ‘हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणास्त्रोत’बुकलेट के अंतर्गत वर्तमान में 4 संस्करण तैयार किये गए हैं, जिनमें प्रदेश के 235 शिक्षकों के विचारों, अकादमिक प्रयासों को संकलित किया गया है।
- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के दृष्टिगत सी. एम. राइज शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के एक महत्त्वपूर्ण घटक में शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों को सतत् रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल पर कुल 49 गुणवत्तापूर्ण डिजिटल प्रशिक्षण संचालित किये गए हैं।
- यह शिक्षकों को डिजिटल माध्यमों से उनकी गति के अनुसार रोचक और आनंदमय तरीके से सीखने-सिखाने की विधियों तथा विषयवार कठिन अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।